(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने होप्स के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई निश्चित उपाय किए हैं;

(ख) क्या देश में होप्स का कुल आन्तरिक उत्पादन इसकी कुल मांग को पूरा कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक सम्भव हो पाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हाँ । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में होप्स के विकास हेतु 1992-93 के दौरान 51.33 लाख रुपए दिए । खादय प्रसंस्करण मंत्रालय ने भी हिमाचल प्रदेश में 1991-92 के दौरान होप्स के विकास और प्रसंस्करण हेतु 40 लाख रुपए की अनुदान-सहायता दी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उद्योग की होप्स सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता लगभग 500 मी० टन है, जबकि कुल उत्पादन लगभग 250 मी० टन है । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की प्राप्ति से देश 1996-97 तक घरेलू आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने में समर्थ हो जाएगा ।

Agricultural University In North-East Region of Country

1550. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) Whether construction work of the Agricultural University proposed to be set up in the East-Northern States, has commenced; and

(b) If so, by when this University is likely to start functioning and what arrangements have so far been made in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) The construction work of the Central Agricultural University for NEH Region has not yet been started.

(b) The Vice-Chancellor of the University has been appointed and as soon as he assumes charge, the university would start functioning.

कृषि का विकास और किसानों का कुशल प्रबन्धन

1551. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के विकास और किसानों के सुप्रबंधन के संबंध में कृषि समिति, 1991-92 की पांचवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिफारिश सं० 1

1.4 समिति ने देखा है कि मानवीय तथा पशुधन की संख्या के दबाव के कारण इतने बड़े क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली चिन्तनीय दर पर खराब हो रही है और इसलिए व्यापक वर्षा सिंचित भूमि पर पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्बहाली देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

1.8 इस तथ्य को देखते हुए कि वर्षा सिंचित क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद के 9.0% का योगदान करते हैं और कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के 25.7% का योगदान करते हैं और लगभग 42.2 प्रतिशत जनसंख्या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली से आजीविका चलाती है, समिति सरकार से पुरजोर सिफारिश करती है कि वे देश की अस्थिर कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिये वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा आर्थिक व्यवस्था के समुत्थान की प्रक्रिया आरम्भ करें ।

इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा निर्यात के सुधार के लिए वर्षा सिंचित खेती की महत्वपूर्ण भूमिका तथा अत्यधिक सम्भावनाओं को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास पूर्वनिर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना चाहिए ।

कार्यवाही:—

1.4 इस समय चल रही पनधारा विकास परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य देश के विशाल वर्षापोषित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनर्बहाली करना है ।

कार्यवाही:—

1.8 पनधारा विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । आठवीं योजना में वर्षापोषित क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा कई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं । इस समय वर्षापोषित क्षेत्रों